

**Fourteenth Loksabha**

**Session : 8**

**Date : 23-08-2006**

**Participants : [Majhi Shri Shankhlal](#)**

an>

Title : Need to release the share of funds to Uttar Pradesh as recommended by the 12<sup>th</sup> Finance Commission.

श्री शंखलाल माझी (अकबरपुर) : सभापति महोदय, शिक्षा और स्वास्थ्य संविधान के दो मौलिक अधिकार हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार अपने सीमित संसाधनों के होते हुये शिक्षा और स्वास्थ्य मुहैया कराने का काम कर रही है। पिछले साढ़े आठ सालों के किसानों के बकाया 1100 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, सड़कों का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले 58 साल के इतिहास में पुल और सड़कें बनाने का एक नया इतिहास रचने का काम किया है। पिछले दो साल में 700 दिनों में 350 पक्के पुल बनाये गये हैं। यह सब उत्तर प्रदेश की सरकार सीमित संसाधनों के होते हुये कर रही है। मैं इस बात की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जब से केन्द्र में यू.पी.ए. की सरकार आई है, यह उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव कर रही है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का छठा हिस्सा है लेकिन 12वें वित्त आयोग ने विकास के लिये जो धन आबंटित किया है, वह आज तक उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं दिया गया है। मेरी आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग है कि उत्तर प्रदेश का बकाया धन शीघ्र आबंटित किया जाये।